युवा सहकार

www.nycsindia.com

जुलाई 2024, नई दिल्ली

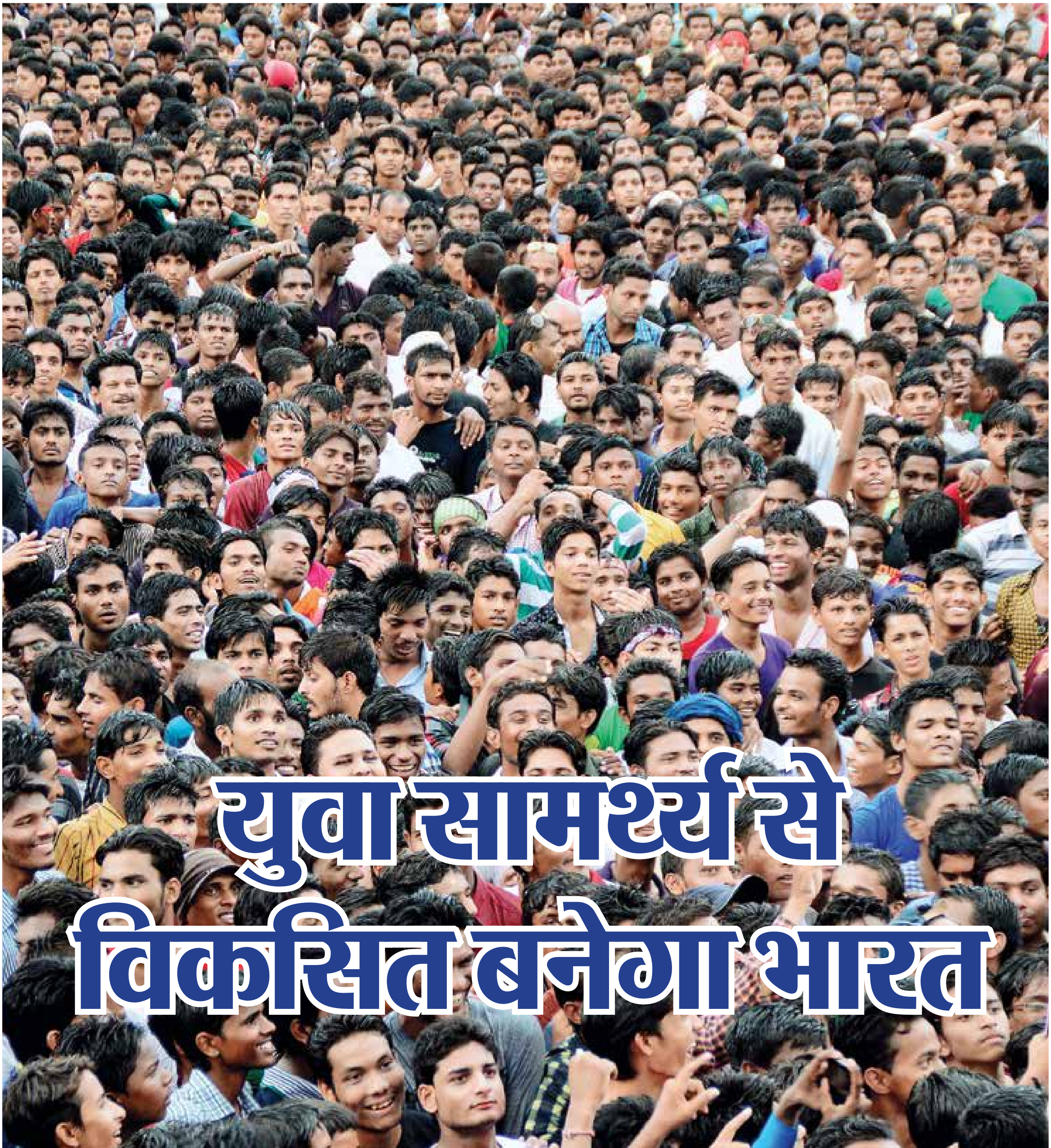

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
IFFCO KISAN DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
IFFCO
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-01, जुलाई-2024

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं पारस ऑफसेट प्रा. लि. कुंडली, हरियाणा द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार राठौड़: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

@NYCSIndia

युवा सामर्थ्य से विकसित बनेगा भारत 06
युवाओं के सपने होंगे साकार 10
डिजिटलीकरण से सहकारी संस्थाओं में बढ़ी पारदर्शिता 12

16 उत्तराखंड सरकार का फैसला, सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण

18 अन्न भंडारण योजना सहकारिता क्षेत्र का क्रांतिकारी कदम

सहकारिता क्रांति का युग 20
युवा विकास से राष्ट्र का विकास 22
सहकार से साकार हो रहा युवाओं का साझा लक्ष्य 24
सहकार बिना जीवन नहीं, युवा बिना सहकार नहीं 27

राष्ट्र विकास में युवाओं की भागीदारी

युवाओं के समुचित विकास के लिए उन्हें कुशल व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा कर उद्यमशीलता के मार्ग पर प्रशस्त करना होगा ताकि युवा वर्ग न केवल अपना, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का विकास करने में समर्थ बने।

पिछले कुछ वर्षों में विश्व में भारत की एक नई पहचान बन रही है। भारत को आज विश्व के सबसे युवा देशों में से एक के रूप में जाना जाने लगा है। यहां की करीब 40 प्रतिशत जनसंख्या 15-35 वर्ष की आयु की है, जबकि करीब 66 प्रतिशत (80 करोड़ से ज्यादा) जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। युवाओं की इतनी बड़ी आबादी के कारण ही भारत अधिक से अधिक सक्षम बनता जा रहा है। इन युवाओं में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा उन युवाओं का है जो कुछ नया सीखकर, नए क्षेत्रों, नए व्यवसायों और नए अवसरों का उचित प्रयोग करते हुए देश की उन्नति में अपना योगदान देने की क्षमता रखते हैं।

भारत की युवाशक्ति को सही दिशा देने और उनकी क्षमताओं का उपयोग विकसित राष्ट्र बनाने में करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री की सोच है कि हर युवा को सीखने, कौशल विकास और कुछ नया करने का अवसर मिले तभी हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के पीछे एक प्रेरक शक्ति हैं। उनका नवाचार रचनात्मकता और उत्साह उन्हें सतत विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में 'सहकार से समृद्धि' का मंत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिसे युवाओं की सुनिश्चित भागीदारी के बगैर हासिल करना मुश्किल है।

युवाओं के समुचित विकास के लिए उन्हें कुशल व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा कर उद्यमशीलता के मार्ग पर प्रशस्त करना होगा ताकि युवा वर्ग न केवल अपना, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का विकास करने में समर्थ बने। युवा विकास से राष्ट्र विकास के सूत्र को अपना ध्येय मानते हुए नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने और ऐसे सभी मौकों से अवगत कराने का प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आ सके।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एनवाईसीएस ने 'युवा सहकार' पत्रिका का नए प्रारुप में प्रकाशन शुरू करने का फैसला किया। इस मासिक पत्रिका के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आ सकेगा, बल्कि सरकार द्वारा युवाओं के लिए लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं अन्य अद्यतन जानकारियां भी लगातार दी जाएंगी जिसका फायदा युवा उठा सकेंगे। उम्मीद है कि एनवाईसीएस का यह प्रयास युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और देश के उज्ज्वल भविष्य के सपने को साकार करने का एक माध्यम बनेगा। ■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

युवा इंजीनियरों का कमाल

छोटे किसानों के लिए बनाया कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर

सीएसआईआर-सीएमईआरआई के युवा इंजीनियरों ने छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 9 हॉर्स पावर का एक कॉम्पैक्ट, किफायती और आसानी से चलने वाला ट्रैक्टर विकसित किया है।

युवा सहकार टीम

खेती में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार इनोवेशन हो रहे हैं। नई मशीनरी और तकनीक के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे न सिर्फ किसानों को समय एवं लागत की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें पहले की तुलना में फायदा भी ज्यादा हो रहा है। छोटे एवं सीमांत किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए देश के युवा इंजीनियरों ने उनके लिए कम हॉर्स पावर वाला कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर बनाया है।

काउंसिल ऑफ साईंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च - सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-सीएमईआरआई) के युवा इंजीनियरों ने डीएसटी के एसईईडी प्रभाग के सहयोग से सीमांत और छोटे किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम हॉर्स पावर का एक कॉम्पैक्ट, किफायती और आसानी से चलने वाला ट्रैक्टर विकसित किया है। यह ट्रैक्टर छोटे और सीमांत किसानों की लागत कम रखते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। किसानों को आपूर्ति के लिए इस ट्रैक्टर का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

इस ट्रैक्टर को 9 एचपी डीजल इंजन के साथ विकसित किया गया है। इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्पीड, 540 आरपीएम पर 6 स्प्लिन के साथ पीटीओ है। ट्रैक्टर का कुल वजन लगभग 450 किलो है। इसका व्हीलबेस, ग्राउंड क्लीयरेंस और टर्निंग रेडियस क्रमशः 1200 मिमी, 255 मिमी और 1.75 मीटर है।

सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने इस कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर के तकनीक का प्रदर्शन किसानों और विभिन्न निर्माताओं के सामने किया है। झारखंड के रांची स्थित एक एमएसएमई ने इसके उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करके इसके निर्माण में रुचि दिखाई है। यह एमएसएमई विभिन्न राज्य सरकार की निविदाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दरों पर ट्रैक्टर की आपूर्ति करने की योजना बना रही है। सीएसआईआर-सीएमईआरआई बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए स्थानीय कंपनियों को इसका लाइसेंस देने पर भी विचार कर रहा है, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा स्थानीय किसानों तक पहुंच सके। संस्थान ने कई मौजूदा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के बीच भी इस तकनीक को बढ़ावा दिया है। साथ ही, इस तकनीक के लिए विशेष रूप से नए एसएचजी बनाने के प्रयास किए गए हैं।

भारत में 80 प्रतिशत से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान हैं। उनमें से आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैलों से खेती करने पर निर्भर है। इन किसानों के लिए परिचालन लागत, रखरखाव और खराब रिटर्न एक चुनौती है। हालांकि पावर टिलर बैलों से चलने वाले हल की जगह ले रहे हैं, लेकिन उन्हें चलाना बोझिल काम है। दूसरी ओर, बड़े ट्रैक्टर काफी महंगे होते हैं जो छोटे किसानों के लिए अनुपयुक्त हैं। इनकी तुलना में कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर से खेती में तेजी आएगी, बैल से जुताई करने में लगने वाले ज्यादा समय की तुलना में कुछ ही समय में खेतों की जुताई हो जाएगी। इससे छोटे रकबे वाले खेतों की जुताई में मदद मिलेगी। इससे किसानों की पूंजी और रखरखाव लागत भी कम हो जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों के लिए बैल से चलने वाले हल की जगह यह किफायती कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर ले सकता है। ■

युवा सामर्थ्य से विकसित बनेगा भारत

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास करने सहित कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है।

भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या हुई 1.40 लाख से ज्यादा, जिनमें 67 यूनिकॉर्न हैं

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सरकार के संकल्प से भारत बना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था

युवा सहकार टीम

विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारीशक्ति और किसान सशक्त होंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं में इन्हीं चार स्तंभों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों और अगले 5 वर्षों के कार्यकाल की रूपरेखाओं को परिलक्षित करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र के अपने अभिभाषण में कहा कि आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्पों में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां हैं, ये इस बात का प्रमाण हैं कि आने वाला दौर भारत का है। ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाव आने वाले एक हजार वर्षों तक रहेगा।

वर्तमान में भारत की बड़ी आबादी युवाओं की है और युवाओं के सामर्थ्य के बूते

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 100वें वर्ष 2047 में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का लक्ष्य रखा है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने न सिर्फ युवा केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता में रखा है, बल्कि उसे समयबद्ध रूप से अमल में लाने पर भी जोर दिया है ताकि उसका बेहतर फायदा उठाया जा सके। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास करने सहित कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र कर स्पष्ट कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता में युवाओं की कितनी भूमिका है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और बढ़ाने के लिए 'मेरा युवा भारत – MY Bharat' अभियान की शुरूआत की गई है। इसमें अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। इस पहल से युवाओं में नेतृत्व कौशल और सेवा भावना का बीजारोपण होगा। बीते 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने ऐसे हर अवरोध को हटाया है जिसके कारण युवाओं को परेशानी हो रही थी। आगे भी इस तरह के और कदम उठाए जाने के संकेत राष्ट्रपति ने दिए।

स्टार्टअप्स को बढ़ावा

केंद्र सरकार के प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। न सिर्फ सामान्य क्षेत्र, बल्कि सैन्य क्षेत्र में भी स्टार्टअप को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर सैन्य क्षेत्र की मजबूत नींव तैयार की गई है। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, इस वक्त डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 1.40 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 67 यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप उसे कहा जाता है जिसका वैल्यूएशन एक अरब डॉलर या इससे ज्यादा होता है। पिछले 10 वर्षों में स्टार्टअप को सरकार ने कितना बढ़ावा दिया है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 में देश में सिर्फ 350 स्टार्टअप थे। एक सर्वे के अनुसार, देश के मौजूदा स्टार्टअप्स ने करीब 15 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया है। पहली बार देश के युवाओं को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने यह समझाने का प्रयास किया कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने आजीविका के ऐसे नए तरीकों को बढ़ावा दिया है जो सरकारी नौकरी से अधिक आकर्षक हो सकते हैं।

नई शिक्षा नीति

नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार ने स्थानीय मातृभाषाओं में पढ़ाई की सुविधा

आत्मनिर्भर कृषि

भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। कृषि क्षेत्र में देश ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ सरकार ने नीतियां बनाई हैं और उस पर प्रतिबद्धता से अमल कर रही है। सरकार दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को हर संभव मदद दे रही है। साथ ही, ग्लोबल मार्केट में किस तरह के खाद्य पदार्थों की मांग ज्यादा है, उसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। भारत के मोटे अनाज (श्री अन्न) की पहुंच सुपरफूड के तौर पर दुनिया के कोने-कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स इयर मनाया। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी।

- सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को दे रही बराबर महत्व।
- पीएलआई स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे जिससे युवाओं को हो रहा फायदा।
- पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर दिया जा रहा बढ़ावा।
- सर्विस सेक्टर को मजबूत बनाने की पहले से आईटी से लेकर टूरिज्म, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक हर सेक्टर में भारत बन रहा लीडर।

उपलब्ध कराने का कदम उठाया है। साथ ही युवाओं को अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प भी मिला है। पिछले 10 वर्षों में देश में 7 नए आईआईटी, 16 नए आईआईआईटी, 7 नए आईआईएम, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। अगले पांच वर्षों में सरकार की कोशिश इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या को और बढ़ाने की होगी। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियान युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था को रफ्तार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले पांच वर्षों में आर्थिक सुधार की गति को और तेज किया जाएगा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सरकार के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसी की बदौलत 10 वर्ष में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर पांचवें नंबर पर पहुंच चुका है। वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2024 के बीच भारत ने औसतन 8 प्रतिशत की दर से विकास किया है। विकास की यह रफ्तार सामान्य समय में नहीं हुई है। वैश्विक महामारी के दौर और विश्व के अलग-अलग कोनों में चल रहे संघर्षों के बावजूद भारत ने यह विकास दर हासिल की है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। अब भारत विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने का काम करेगी।

महिला सशक्तिकरण का युग

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि महिला केंद्रित विकास के लिए समर्पित केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरूआत की है। देश की नारीशक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आज उनके पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ताकत है। इसके अलावा, सरकार की विभिन्न योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। पिछले 10 वर्ष में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आवंटित हुए हैं। शहरी और ग्रामीण गरीबों को पक्का घर देने की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 3 करोड़ नए

घर और बनाए जाएंगे। सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरूआत में ही इसकी स्वीकृति दे दी है। इनमें से भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर ही आवंटित होंगे।

महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का एक व्यापक अभियान चलाया है। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, आमदनी के साधन बढ़ें और उनका सम्मान बढ़े। इसके लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरूआत की है जो इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है। इस योजना के तहत 15 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिए जा रहे हैं और उन समूहों की महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

सरकार ने हाल ही में कृषि सखी कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके तहत अभी तक स्वयं सहायता समूहों की 30 हजार महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण-पत्र दिए गए हैं। कृषि सखियों को आधुनिक खेती की तकनीक में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे कृषि को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सकें। सरकार का ये भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सकें। इसके लिए बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है जो काफी लोकप्रिय है। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना से भी महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है और उनकी जिंदगी पहले से आसान हुई है।

सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के लाभार्थियों तक पहुंचाए जाने के सफल प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग सहित समाज के हर क्षेत्र के परिवार शामिल हैं। विशेषकर आदिवासी समाज में यह बदलाव और भी स्पष्ट नजर आ रहा है।

बीते 10 वर्ष में ऐसे अनेक सुधार हुए हैं जिनका लाभ आज देश और यहां के लोगों को मिल रहा है। इन्हीं में शामिल है बैंकिंग क्षेत्र में किया गया सुधार। कोऑपरेटिव बैंकों सहित सभी तरह के बैंकों को डूबने से बचाने के लिए आईबीसी जैसे कानून बनाए गए हैं जिससे बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिली है। इन सुधारों की वजह से देश का बैंकिंग सेक्टर अब दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सेक्टर्स में एक बन गया है। अब जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए हैं तो इन सुधारों में और भी तेजी आएगी जिससे विकसित भारत बनाने के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। ■

सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

केंद्र सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की व्यापक पहल कर रही है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया है। गांवों में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। किसान उत्पाद संघ (एफपीओ) और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा है। जिन पंचायतों में पैक्स नहीं हैं वहां पैक्स का गठन किया जा रहा है। डेयरी और फिशरीज क्षेत्र सहित अतिरिक्त 2 लाख पैक्स बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। अगले पांच वर्ष में सहकारिता क्षेत्र भारत की आर्थिक उन्नति की गाथा लिखेगा। भंडारण छोटे किसानों की बड़ी समस्या है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर काम शुरू कर दिया है। कोऑपरेटिव के माध्यम से इस योजना को अमल में लाया जा रहा है। इसका फायदा न सिर्फ किसानों को मिलेगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे और सहकार से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

युवा सहकार टीम

भारत अब युवाओं का देश है। युवाओं की बड़ी आबादी को देखते हुए सरकार की चुनौतियां भी बड़ी हैं। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में शहर से लेकर गांवों तक में युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कराने, उनका कौशल विकास करने, युवा उद्यमी बनाने सहित कई योजनाओं को लागू किया हैं। अब जब तीसरी बार वह सत्ता में लौट आए हैं तो इन कदमों को और पंख लगेंगे जिससे युवाओं के सपनों को पूरा करने सहित भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री की सोच है कि हर युवा को सीखने, कौशल विकास और कुछ नया करने का अवसर मिले तभी हम 2047 तक सपनों के भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री युवाओं की शक्ति को वैश्विक संपत्ति के रूप में देखते हैं। उनका दृष्टिकोण युवाओं को सशक्त बनाना और भारत की प्रगति एवं दुनिया की भलाई के लिए उनकी क्षमताओं का उपयोग करना है।

उनके प्रयासों में स्किल इंडिया शामिल है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देना और स्टार्टअप का समर्थन करना है, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, अटल इनोवेशन मिशन छात्रों के बीच नवाचार और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया का उद्देश्य देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करना है। ये कदम सामूहिक रूप से युवाओं का व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास कर आवश्यक अवसर प्रदान कर रहे हैं जो अंततः भारत के समग्र विकास में योगदान दे रहे हैं।

समावेशी निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए शासन में युवाओं की भागीदारी आवश्यक है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने मंत्रिमंडल में युवाओं को अधिक भागीदारी दी है।

मंत्रिमंडल की औसत उम्र घटी

युवाओं से जुड़े सरोकार पर नई सरकार का ध्यान कितना रहेगा इसका अंदाजा मंत्रिमंडल के औसत उम्र से भी लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बार कम उम्र के ज्यादा सांसदों को सरकार में जगह दी है जिससे मंत्रिमंडल की औसत उम्र घटकर 58 साल रह गई है। 2019 में नई सरकार के गठन के समय मंत्रिमंडल की औसत उम्र 61 साल थी। 2014 में मंत्रिमंडल की औसत उम्र 60 वर्ष थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी एनडीए सरकार में तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के 36 वर्षीय के. राममोहन नायडू और बीजेपी की 37 वर्षीय रक्षा खड़से सबसे कम उम्र के मंत्री हैं, जबकि 76 वर्षीय जीतनराम मांझी सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर एनडीए सरकार में 12 से ज्यादा चेहरे 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं। नई सरकार में कुल 71 मंत्री हैं जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्री हैं। इन मंत्रियों में 7 महिलाएं शामिल हैं।

हालांकि, चिंता की बात यह है कि 18वीं लोकसभा में 25-40 वर्ष के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 11 प्रतिशत रह गई है। पहली लोकसभा में इनकी संख्या 33.5 प्रतिशत थी। इसके उलट इस बार की लोकसभा सबसे उम्रदराज हो गई है जिसमें सांसदों की औसत उम्र 56 वर्ष है जो अब तक की सबसे ज्यादा है। पहली लोकसभा के सांसदों की औसत उम्र 46.5 वर्ष थी।■

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में वापसी से उन योजनाओं में तेजी आएगी जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लागू की हैं।

डिजिटलीकरण से सहकारी संस्थाओं में बढ़ी पारदर्शिता

सहकारिता क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे युवा

सहकारिता मंत्रालय का प्राथमिक समितियों से होने लगा सीधा संवाद

तथ्यों और जानकारियों के लिए अब किसी का मोहताज नहीं पैक्स

जागरूकता बढ़ने से सहकारिता के प्रति युवाओं में बढ़ा आकर्षण

युवा सहकार टीम

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी आंदोलन को देशव्यापी और जनव्यापी बनाने का फैसला जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। साढ़े आठ लाख से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जुड़े 29 करोड़ से अधिक लोगों को सहकारिता के प्रति जागरूक बनाने की अपील को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने इसे निरंतर आगे बढ़ाया है। डिजिटलीकरण से सहकारिता में जहां पारदर्शिता बढ़ी है, वहीं विश्वसनीयता मजबूत हुई है। सहकारिता में लोगों का भरोसा बढ़ा है जिससे खासकर देश के युवा इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं।

सूचना, संचार व प्रसार से लोगों में सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जबकि डिजिटलीकरण से पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिला है। इससे सहकारिता जीवंत और सुदृढ़ हुई है। सहकारिता को सुगम बनाने और लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। इससे जहां गरीबों, वंचितों और किसानों के जीवन में बदलाव आने लगा है, वहीं युवाओं और महिलाओं के लिए यह क्षेत्र आकर्षण का केंद्र बनने लगा है। युवा उद्यमियों को सहकारिता के माध्यम से भरपूर सहयोग

मिलने लगा है। पिछले 70 वर्षों के दौरान सहकारिकता लक्ष्य से भटककर सीमित हाथों में पहुंच गई थी। राजनीति का अड्डा बन गई सहकारिता को वहां से निकालकर आम लोगों के हाथों में सौंपने की मुहिम को इससे बल मिला है। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और हितधारकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने जबर्दस्त पहल की है। इसके तहत सूचनाएं और तथ्यपरक जानकारी प्रेषित करने के लिए मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्म का बखूबी उपयोग किया जा रहा है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की नीतियों के साथ की गई पहलों से लोगों को जागरूक बनाने में सूचना, संचार व प्रसार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। मंत्रालय का इस बात पर विशेष जोर रहा है कि सहकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी निचले स्तर तक समय से पहुंचनी चाहिए। मुख्यधारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर सहकारिता से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इसी वजह से सहकारिता से जुड़ी हर तरह की जानकारी लोगों तक समय पर पहुंच रही है। सहकारी आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की नीतियां कारगर साबित हो रही हैं।

केंद्र के साकारात्मक कदम

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से इन दो वर्षों में 54 महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं, जिसमें नीतिगत फैसलों के अलावा कई और पहलें शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से आम लोगों के हित में किए गए नीतिगत फैसलों की जानकारी तत्क्षण लोगों तक पहुंचाने में सूचना व संचार विंग तत्पर है। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पैक्स) से लेकर सहकारी संस्थाओं के हित में कदम उठाए गए हैं। पैक्स के कामकाज को पारदर्शी बनाने और उन्हें राज्य और केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालयों और नाबार्ड से जोड़ने के लिए उनका कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसी तरह उनकी कार्य प्रणाली को और मजबूत बनाने के साथ उनके कारोबार का दायरा बढ़ाने के भी फैसले किए गए हैं।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स में सुधार के लिए मॉडल बायलॉज तैयार कर सभी राज्यों को भेजा है। राज्यों ने मॉडल बायलॉज की उपयोगिता को समझते हुए उसे आगे बढ़कर अपनाया है। राज्यों में इस पर अमल कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इससे सहकारिता की निचली इकाई पैक्स की आमदनी में जहां वृद्धि हुई है, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में भी मदद मिली है। देश के शत प्रतिशत पैक्स के डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए उनका कंप्यूटरीकरण अंतिम चरण में है।

मंत्रालय की तरफ से उठाए गए इन कदमों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने में सहकारिता मंत्रालय का सूचना, संचार व प्रसार विभाग त्वरित गति से कार्य कर रहा है। मंत्रालय में इसके लिए एक बड़ी टीम गठित की गई है, जिसकी समय-समय पर सघन निगरानी सहकारिता सचिव भी करते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करने के लिए उच्चाधिकारियों की टीमें राज्यों में दौरा कर रही हैं। पैक्स के सक्रिय होने से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने लगी है।

मजबूत हुआ बुनियादी ढांचा

केंद्र सरकार ने सहकारिता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा बल दिया है। इसमें सहकारिता के प्रति लोगों को जागरूक बनाना उच्च प्राथमिकता में शामिल है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने मजबूत सूचना व संचार टीम का गठन किया है। इसकी देखरेख में विभिन्न सूचना व संचार माध्यमों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। प्रिंट मीडिया में अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर जबर्दस्त अभियान चलाया गया। सहकारिता क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को प्रमुखता के साथ खबरों और विज्ञापनों के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सम्मेलनों का आयोजन कर उसमें सहकारिता से जुड़े लोगों को आमंत्रित कर उन्हें सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया जा रहा है।

मंत्रालय द्वारा की गई पहल

- मंत्रालय द्वारा की गई मुख्य पहलों का समय-समय पर संकलन कर दस्तावेज तैयार किया गया एवं उसे अपडेट कर 13 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।
- मंत्रालय की मुख्य पहलों पर पुस्तिका भी तैयार की गई, जिसे सभी हितधारकों को समय-समय पर भेजा गया।
- सभी हितधारकों को मंत्रालय की पहलों की बेहतर जानकारी के लिए मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से प्रजेंटेशन किया गया।
- सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद 6 जुलाई, 2021 से अब तक 40 से अधिक बड़े सहकारिता सम्मेलन हो चुके हैं। इनमें राष्ट्रीय सहकारी संघों के राष्ट्रीय स्तर के 14 सम्मेलन भी शामिल हैं। इन सम्मेलनों का जमकर प्रचार व प्रसार किया गया।
- 12 व 13 अप्रैल, 2022 को राज्यों के सहकारिता सचिवों, पंजीयकों एवं राष्ट्रीय संघों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। इसमें सहकारिता में सुधार के लिए उठाए कदमों की जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई।

सहकारी योजनाओं को सूचना एवं संचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया

- एक जून 2022 को सहकारी समितियों को जेम पोर्टल पर खरीदार और विक्रेता के रूप में पंजीकृत कर पारदर्शी और बाजार की प्रतिस्पर्धा में शामिल किया गया।
- 29 जून, 2022 को 62,318 पैक्स के कंप्यूटरीकरण को मिली मंजूरी। उन्हें एकल कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क, आईटी, जीएसटी रिटर्न, ऑडिट और नाबार्ड से लिंकिंग की सुविधा मिली।
- 12 अक्टूबर, 2022 को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में 97वां संविधान संशोधन के अनुपालन, चुनाव सुधार, पारदर्शिता, व्यापार की सुगमता, निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण हेतु संशोधन बिल संसद से पारित करके 03 अगस्त, 2023 से लागू किया गया।
- 11 जनवरी, 2023 को नई राष्ट्रीय आर्गेनिक समिति के गठन से जैविक उत्पादों के संग्रहण, प्रमाणन, परीक्षण, संवर्धन तथा विपणन को बढ़ावा। समिति को 8 नवंबर, 2023 को औपचारिक तौर से लांच किया गया।

सूचनाओं से लैस हो रही सहकारी संस्थाएं

सहकारिता से संबंधित सरकार के कदमों और दृढ़ फैसलों को लोगों तक पहुंचाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। सहकारिता के प्रचार व प्रसार में इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग किया जा रहा है। परंपरागत मीडिया के साथ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म यूट्यूब, एक्स (ट्वीटर), इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सऐप ग्रुप के सहारे लोगों तक हर उचित सूचना पहुंचाई जा रही है। सहकारिता से जुड़े प्रत्येक सहकार को जोड़ने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के पैक्स सदस्यों को उनके मोबाइल फोन पर समय-समय पर संदेश (एसएमएस) भी प्रसारित किया जाता है। सूचना व संचार विभाग विभिन्न सहकारी संस्थाओं को हर तरह की सूचनाओं से लैस कर रहा है।

पारदर्शिता से बढ़ी जागरूकता

सहकारिता मंत्रालय के कामकाज और प्रक्रियागत बदलावों और अन्य पहलों की तथ्यपूर्ण विस्तृत जानकारी सूचना, संचार और प्रसार की टीम संभालती है। वह पूरी पारदर्शिता के साथ मीडिया के विभिन्न स्रोतों का दोहन करते हुए उसका उपयोग करती है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट और उससे जुड़ी विभिन्न राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों की वेबसाइट को निरंतर अपडेट करने के साथ उसकी निगरानी भी की जाती है। मंत्रालय से संबद्ध सभी कार्यक्रमों की अद्यतन सूचना वेबसाइट पर उलब्ध कराई जाती है। इसीलिए सहकारिता से संबंधित हर तरह की ताजा जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।

सूचना के उपयोग का नायाब उदाहरण

सहारा समूह की सोसाइटियों में जमाकर्ताओं को उनके डूबे धन के भुगतान को लेकर सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न अदालतों में जबर्दस्त पैरवी और उससे संबंधित जानकारी समय-समय पर प्रसारित की गई है। इससे सहारा समूह की सोसाइटियों में जमा धन के भुगतान की शुरूआत हो चुकी है। इस बारे में सूचना व संचार विभाग पहले एक्स (ट्वीटर) और फिर अन्य मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से यह सूचना लोगों तक पहुंचा रही है। सहारा समूह की सोसाइटियों से भुगतान को लेकर छोटी-छोटी जानकारी भी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। केंद्रीय रजिस्ट्रार की निर्धारित वेबसाइट पर लगातार जमाकर्ताओं का ट्रैफिक बढ़ रहा है। मंत्रालय भी इसे अपडेट कर रहा है।

संवाद कौशल की कामयाबी

क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट का

सहकारिता को बजटीय सहायता

- ❒ कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में आयकर कानूनों में समुचित रियायतें दी गईं, जिससे सहकारी संस्थाएं फल फूल रही हैं।
- ❒ आम बजट 2022-23 में सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- ❒ वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में सहकारी चीनी मिलों के लिए एक अप्रैल 2016 से पहले की आयकर मांगों का पुनर्मूल्यांकन करके 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राहत प्रदान की गई।
- ❒ स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि की गई। कटौती की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक कर दिया गया। इससे नकदी निकासी पर टीडीएस में छूट दी गई।
- ❒ सहकारी क्षेत्र की नई मैन्यूफैक्चरिंग इकाई के कार्य आरम्भ करने वाली उत्पादक सहकारी समितियों पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।

सहकारिता क्षेत्र का विस्तार

- ❒ दो फरवरी 2023 को सीएससी की 300 से अधिक ई-सेवाएं पैक्स को चलाने की मंजूरी मिली।
- ❒ 13 मार्च, 2023 को नए पेट्रोल और डीजल पंप के आवंटन में पैक्स को प्राथमिकता देने का फैसला।
- ❒ 13 मार्च, 2023 को ही एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पैक्स को पात्रता प्रदान की गई।
- ❒ 13 मार्च, 2023 को मौजूदा थोक पेट्रोल और डीजल लाइसेंसधारी पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने की छूट मिली।
- ❒ 13 मार्च, 2023 को सहकारी चीनी मिलों को एथनॉल खरीद के लिए अन्य निजी कंपनियों के अनुरूप प्राथमिकता प्रदान की गई।
- ❒ एक मई 2023 को मौजूदा पैक्स को किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
- ❒ 25 मई, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिसूचना जारी कर समस्याओं के निवारण हेतु अपना अधिकारी नामित किया।

10 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी डीसीडीसी द्वारा जिला स्तर पर सहकारिता संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से भी मंत्रालय द्वारा लघु रील्स बनाकर, सरकार की पहलों की जानकारी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मंत्रालय की पहलों पर हिंदी में नुक्कड़ नाटक तैयार कर 10 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर मंचन किया जा रहा है। इसी क्रम में 12 भाषाओं में मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से दिसंबर 2024 तक पत्रिकाओं का सकुर्लेशन तीन गुना तक करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से अभी 1.25 लाख लोग जुड़े हैं, दिसंबर 2024 तक इस संख्या को दस लाख तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। छात्रों को शुरूआती स्तर पर ही सहकारिता की शिक्षा मिल सके इस उद्देश्य से एनसीईआरटी की किताबों में सहकारिता विषय पर एक अध्याय शामिल करने की भी कोशिश की जाएगी। छात्रों में सहकारिता की समझ विकसित करने और सहकारिता के प्रति आकर्षण के लिए सीबीएसई स्कूलों में सहकारिता क्लब की स्थापना की जाएगी।

अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सहकारिता मंत्रालय के यूट्यूब चैनल से लगभग एक दर्जन से अधिक कार्यक्रमों और आयोजनों का सजीव प्रसारण किया गया, जिसे एक करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। मंत्रालय की पहलों व कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में तीन हजार से अधिक खबरें प्रकाशित की गईं। मंत्रालय की वेबसाइट को उससे जुड़ी स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 1.19 करोड़ लोगों ने देखा है।■

छात्रों को शुरूआती स्तर पर ही सहकारिता की शिक्षा मिल सके इस उद्देश्य से एनसीईआरटी की किताबों में सहकारिता विषय पर एक अध्याय शामिल करने की भी कोशिश की जाएगी। छात्रों में सहकारिता की समझ विकसित करने और सहकारिता के प्रति आकर्षण के लिए सीबीएसई स्कूलों में सहकारिता क्लब की स्थापना की जाएगी।

उत्तराखंड सरकार का फैसला

सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण

सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी बैंकों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड

सहकारिता विभाग की सभी 670 समितियों की प्रबंध कमेटी में महिलाओं को भागीदारी का मिलेगा मौका

युवा सहकार टीम

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों में पारदर्शिता बढ़ाने, प्रबंधन समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने और परिवारवाद को समाप्त करने के लिए सहकारी समितियों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना आवश्यक बनाया है। इससे महिलाओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचारों और अनुभवों की विविधता आएगी, महिलाओं की भागीदारी से सहकारिता के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी और संतुलित निर्णय लिए जा सकेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों और कोऑपरेटिव बैंकों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सहकारी संस्थाओं की प्रबंध समिति के सदस्य और सभापति पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2004 में संशोधन को मंजूरी दी है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारी समितियों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की यह बड़ी पहल है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से सहकारिता के संचालन, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलेगा। इस निर्णय से इन संस्थाओं में एकल परिवारों के वर्चस्व की समस्या भी खत्म हो जाएगी और महिलाएं सहकारी संस्थाओं के कामकाज में एक अनूठा दृष्टिकोण और योगदान दे सकेंगी। इस बड़े निर्णय से सहकारी समितियों में उच्च स्तरों पर निदेशक मंडल और अध्यक्ष के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थान मिलेगा। श्री रावत ने कहा कि राज्य में 10 जिला सहकारी बैंक, शीर्ष सहकारी संस्था, 670 बहुउद्देशीय सहकारी समिति (एमपैक्स) संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें नेतृत्व के पदों पर महिलाओं की भागीदारी कम है। ऐसे में, सहकारी संस्थाओं में लैंगिक समानता की दिशा में राज्य सरकार ने यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इस फैसले से प्रदेश में करीब चार हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी और लगभग 260 समितियों को महिला पदाधिकारी मिलेंगी। जिला सहकारी बैंकों में 50 महिलाएं और प्रदेश की 14 शीर्ष सहकारी समितियों में भी करीब 70 महिलाएं डायरेक्टर बनेंगी। उत्तराखंड राज्य सहकारी क्षेत्र में नेतृत्व के पदों पर लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काफी समय से लगातार प्रयास कर रहा है। देश के कई अन्य राज्यों की तरह यह राज्य भी लैंगिक असमानता और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी के मुद्दों से लंबे समय से जूझ रहा है। सहकारी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से उनके संचालन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।■

उत्तराखंड की सहकारी समितियों की एसआईटी जांच

युवा सहकार टीम

देश भर की सहकारी समितियों का डेटाबेस बनाने और उनका कम्प्यूटराइजेशन करने के केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के कदम से सहकारी समितियों में फैली गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। कम्प्यूटरीकरण किए जाने के बाद उत्तराखंड की कई सहकारी समितियों में वित्तीय गड़बड़ियों का पता चला है जिसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड के सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर पर कराई गई जांच में गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है। इसी के बाद विस्तृत जांच का आदेश दिया गया है। जांच के दायरे में राज्य की कई सहकारी समितियां आएंगी। अभी तक सहकारी समितियों का पूरा हिसाब-किताब मैनुअल खातों में ही संचालित होता था। पहली बार केंद्र सरकार की योजना के तहत सभी सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया गया। सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होते ही गड़बड़ियां पकड़ में आने लगी हैं।

उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, उन सहकारी समितियों के खिलाफ एसआईटी जांच के निर्देश दिए गए हैं जिनमें वित्तीय अनियमितता पाई गई हैं। वित्तीय लेन-देन में हेराफेरी करने वाले विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अगर दोषी पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किए जाने से बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला। समय-समय पर सरकार को विभिन्न माध्यमों से इसकी सूचनाएं मिल रही थीं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पहले विभागीय जांच के निर्देश दिए थे। प्रथम चरण की विभागीय जांच में प्रदेश भर की कई सहकारी समितियों में घपले एवं घोटाले के मामले सामने आए। विभागीय जांच में जिन सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता व गबन के मामले पाए गए हैं, उन समितियों के खिलाफ एसआईटी जांच की जाएगी।

- **सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण से उत्तराखंड की कई समितियों में वित्तीय गड़बड़ी आई सामने**
- **प्राथमिक जांच में गबन की पुष्टि होने पर राज्य सरकार ने विस्तृत जांच का दिया निर्देश**

डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, प्रथम चरण की जांच में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी गबन का दोषी पाया गया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा गबन की गई धनराशि को ब्याज सहित वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार घपलेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सहकारी समितियों का संचालन पारदर्शी तरीके से करने को प्रतिबद्ध है ताकि आम लोगों को सहकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

सहकारिता मंत्री का कहना है कि अभी एसआईटी जांच सिर्फ कुछ ही समितियों की होगी। जरूरत पड़ी तो जांच का दायरा बढ़ाते हुए अन्य सहकारी समितियों की भी पड़ताल की जाएगी।

इन समितियों की होगी जांच

विभागीय जांच में जिन सहकारी समितियों में आर्थिक अनियमितता का पता चला है उनमें पौड़ी जनपद में डाण्डामंडी व चांदपुर एम्पैक्स, देहरादून जनपद में विकासनगर, त्यूणी, दसऊ व भानियावाला एम्पैक्स, रूद्रप्रयाग में दैड़ा बहुउद्देश्यीय साधन सहकारी समिति, टिहरी में मेगाधार (भिलंगना), बड़कोट (जाखणीधार), सांदणा (जाखणीधार), पडिया, रौणिया (प्रतापनगर) एम्पैक्स शामिल हैं। इनके अलावा, अल्मोड़ा में फलसीमा व भवाली, उत्तरकाशी में जखौल एम्पैक्स, नैनीताल में ल्योलीकोट व सुयालवाड़ी और ऊधमसिंह नगर में फौजी मटकोटा किसान सेवा सहकारी समिति, रूद्रपुर में घपले की बात सामने आई है। साथ ही, हरिद्वार में बहुउद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति बेल्डा, मंगलौर पूर्वी, खेलपुर, बहुउद्देश्यीय साधन सहकारी समिति जवाहरखान, खेडी सिकोहपुर, जवाहरखान बुजुर्ग, धनपुरा, बहुउद्देश्यीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति सलेमपुर, चमोली में मसोली समिति की भी एसआईटी जांच की जाएगी।■

अन्न भंडारण योजना सहकारिता क्षेत्र का क्रांतिकारी कदम

कृष्ण पाल गुर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

यह योजना जब पूरे भारत में पूरी तरह से लागू हो जाएगी, तो देश में खाद्यान्न भंडारण क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आएगी। हमें सभी हितधारकों के परामर्श से कार्यक्रम गतिविधियों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

भारत में विश्व की कृषि योग्य भूमि का लगभग 11 प्रतिशत उपलब्ध है जिस पर विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 18 प्रतिशत आबादी निवास करती है। 11 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि से भारत की बढ़ती हुई आबादी हेतु खाद्य आपूर्ति की मांग अथवा भोजन की आवश्यकता को पूरा करना और प्रति व्यक्ति अन्न की उपलब्धता को बढ़ाना वर्तमान समय की बड़ी चुनौतियों में से एक है।

इसके लिए यह आवश्यक है कि कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के साथ-साथ कृषि उत्पाद एवं उत्पादकता बढ़ाई जाए। साथ ही कृषि भंडारण की क्षमता को भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान समय में भारत में उत्पादन के सापेक्ष भंडारण क्षमता अन्य देशों की तुलना में कम है। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, रूस जैसे देशों में भंडारण क्षमता कुल उत्पादन का क्रमशः 161%, 150%, 148% और 132% है, जबकि भारत में केवल उत्पादन के सापेक्ष लगभग 47% भंडारण क्षमता है।

भारत में लगभग 14 करोड़ किसान परिवार रहते हैं जिनमें से लगभग 86% छोटे और सीमांत किसान हैं। इन किसानों को उचित भंडारण की कमी के चलते अपने उत्पाद को कई बार मजबूरन कम कीमत पर बेचने को विवश होना पड़ता है। मजबूरन बिक्री जैसे हालात को सुधारने के लिए भंडारण के क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। भारत में भंडारण क्षमता को बढाने के लिए कम्युनिटी स्तर पर लोगो को सामूहिक प्रयास के तहत सहायता की जानी चाहिए।

देश में कुल 1.02 लाख पैक्स हैं जिनमें से लगभग 70,000 पैक्स कार्यशील हैं। वर्तमान समय में 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 22,449 पैक्स में 50 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साधारण गोदाम पहले से बने हुए हैं। अगर कुल पैक्स की संख्या के साथ मौजूदा गोदामों की क्षमता को देखें, तो यह कुल पैक्स की तुलना में 22% तथा कार्यशील पैक्स की तुलना में 32% ही है। इस प्रकार लगभग 78% पैक्स को भंडारण के दायरे में लाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन के सापेक्ष में भंडारण क्षमता की समस्या को दूर किया जा सके। भंडारण में कमी की भरपाई को दूर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्तमान समय में कटाई के बाद 6% फसलों का नुकसान हो जाता है। स्थानीय उपभोग के लिए भंडारण नहीं होने से परिवहन लागत अधिक होती है। इसके साथ ही पंचायत स्तर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा आपूर्ति श्रृंखला का सुगम प्रबंध नहीं हो पता है।

यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पैक्स सहकारी आंदोलन की प्राथमिक संस्था है जो सबसे निचले स्तर पर कार्य करती है। अतः इसको सहकारिता की आत्मा कहा जाता है। देश भर के पैक्स में लगभग 13 करोड़ किसान सदस्य के तौर पर जुड़े हुए हैं। पैक्स जितना मजबूत होगा सहकारी आंदोलन पूरे देश में उतना ही सुदृढ़ होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने सहकारिता की ताकत को पहचाना है। यही कारण है कि उन्होंने सहकारिता से समृद्धि का मंत्र दिया। मंत्र देने के साथ ही इस परिकल्पना को साकार करने के क्रम में सहकारिता मंत्रालय विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना लाया है जिससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- मौजूदा योजना बहुआयामी है। यह न केवल पैक्स स्तर पर गोदामों के निर्माण द्वारा देश में भंडारण के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करेगी, बल्कि पैक्स को कई अन्य गतिविधियां करने के लिए भी

सक्षम बनाएगी, जैसे:

- राज्य एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर्स के रूप में कार्य करना।
- उचित दर की दुकानों (एफपीएस) के रूप में सेवा प्रदान करना।
- कस्टम प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना जिसमें कृषि उपजों की जांच, छंटाई, ग्रेडिंग इकाई आदि शामिल हैं।
- इसके अलावा स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बनने से खाद्यान्न की क्षति कम होगी और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।
- किसानों को विभिन्न विकल्प प्रदान करके फसलों का बहुत कम मूल्य पर आकस्मिक बिक्री रुकेगी और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि और ग्रामीण परिदृश्य को जमीनी स्तर पर बदलने में मदद मिलेगी।
- खरीद केंद्रों और वेयरहाउस से उचित दर पर खरीदगी से खाद्यानों के परिवहन में होने वाले व्यय में भारी कमी आएगी।
- 'Whole of Government' अप्रोच से यह योजना पैक्स को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को विविधतापूर्ण बनाकर सशक्त करेगी। इसके परिणामस्वरुप किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। पैक्स के स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता के साथ-साथ अन्य कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा।

  इससे न केवल देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पैक्स एक वाइब्रेंट आर्थिक संस्था के रूप में कार्य करेगी। इससे समृद्ध, आत्मनिर्भर और खाद्यान्न से संपन्न भारत बनेगा।

योजना का प्रोफेशनल तरीके से समयबद्ध और एकरुपता के साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 चुने हुए जिलों में एक पायलट परियोजना को कार्यान्वित करने जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट इस योजना की विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। इससे इस योजना के देशव्यापी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की चिन्हित योजनाओं के तहत उपलब्ध कराए गए परिव्यय का उपयोग कर समुचित समन्वय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

यह योजना जब पूरे भारत में पूरी तरह से लागू हो जाएगी, तो देश में खाद्यान्न भंडारण क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आएगी। हमें सभी हितधारकों के परामर्श से कार्यक्रम गतिविधियों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास पर इसके दूरगामी सकारत्मक प्रभावों के माध्यम से यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के सपने को साकार करेगी। ■

देश में कुल 1.02 लाख पैक्स हैं जिनमें से लगभग 70,000 पैक्स कार्यशील हैं। वर्तमान समय में 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 22,449 पैक्स में 50 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साधारण गोदाम पहले से बने हुए हैं। अगर कुल पैक्स की संख्या के साथ मौजूदा गोदामों की क्षमता को देखें, तो यह कुल पैक्स की तुलना में 22% तथा कार्यशील पैक्स की तुलना में 32% ही है।

सहकारिता क्रांति का युग

दीनानाथ ठाकुर

राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती

ग्रामीण विकास के रास्ते देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होने वाला है। किसान, गरीब, वंचित, असहाय, महिला और युवाओं के लिए यह क्षेत्र सबसे उपयोगी साबित हो रहा है।

एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने वाली सहकारिता के लिए यह दौर किसी क्रांति से कम नहीं है। सहकारिता क्षेत्र में विश्वास और समर्पण का जो संकट पैदा हुआ था, उसका कुछ-कुछ निवारण होने लगा है। यह संभव हुआ है सहकारिता क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित कानूनी सुधार और आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से। इन सुधारों से सीमित क्षेत्र में सिमटे सहकारिता क्षेत्र को खुला आसमान मिल गया है। इस क्षेत्र का विस्तार हो जाने से सहकारी आंदोलन प्रत्येक वर्ग के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने को पूरी तरह तैयार है। सहकारिता की ठप पड़ी सबसे छोटी इकाई पैक्स से लेकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटियां बन रही हैं। ग्रामीण विकास के रास्ते देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होने वाला है। किसान, गरीब, वंचित, असहाय, महिला और युवाओं के लिए यह क्षेत्र सबसे उपयोगी साबित हो रहा है। फसलों के बीज, ऑर्गेनिक खेती और सहकारी उत्पादों के निर्यात के लिए गठित राष्ट्रीय सहकारी सोसायटियां अब कॉरपोरेट सेक्टर का मुकाबला करने को तत्पर हैं।

सहकारी क्षेत्र की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुग्ध क्षेत्र की सहकारी सोसायटी अमूल और फर्टिलाइजर क्षेत्र की सहकारी सोसायटी इफको विश्व स्तर पर चर्चित ब्रांड बन चुके हैं। देश के कुल फर्टिलाइजर उत्पादन और वितरण में इसकी भूमिका अहम है। चीनी उद्योग सेक्टर में भी सहकारी क्षेत्र ने अपनी धाक जमाई है। हालांकि, चीनी उद्योग क्षेत्र मुट्ठीभर लोगों के हाथ में सिमट गया, जिनका देश की राजनीति में अच्छा खासा दखल रहा। लिहाजा, इस क्षेत्र के सुधार के बारे में कभी विचार ही नहीं किया गया। उत्तर भारत की सहकारी चीनी मिलें लगभग बंद हो चुकी हैं। एक बात और, इन सीमित क्षेत्रों के अलावा सहकारिता का प्रसार अन्य क्षेत्रों में नहीं हो सका, जबकि बैंकिंग से लेकर छोटे-बड़े तमाम क्षेत्रों में इसका प्रभाव था। यह आश्चर्यजनक है कि देश के स्वतंत्र होने के बाद लगभग सात दशक तक सरकारों के स्तर पर सहकारी आंदोलन के सीमित क्षेत्रों तक ही सिमट जाने की वजह जानने की कभी कोई कोशिश ही नहीं की गई।

दरअसल, बीते 60-65 वर्षों में सहकारिता की क्षमता को आंकने का प्रयास ही नहीं किया गया। इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के निर्माण को लेकर भी पिछली सरकारें उदासीन रहीं। परंतु, अब स्थितियों में परिवर्तन हुआ है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सहकारी क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहल अलग से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को इसका दायित्व मिला और इस क्षेत्र पर उनकी गहरी पकड़ ने इस क्षेत्र को तेज गति प्रदान की है। सहकारिता के प्रति एक नई सोच विकसित हुई है और इस क्षेत्र में कानूनी सुधार के क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। घूम फिरकर मुट्ठीभर लोगों के हाथों में सिमटने वाली सहकारी सोसायटियों को खुली हवा में सांस लेने और विकास करने का अवसर मिला है। राज्य स्तर पर निचली इकाई प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) स्तर के बायलॉज बदले गए ताकि इसका दरवाजा सबके लिए खुले। राज्यों ने इसे हाथों हाथ लिया। सदस्यता अभियान चलाया गया।

डिजिटल क्रांति का लाभ लेने के लिए सहकारिता क्षेत्र में इसका खुलकर उपयोग शुरू हुआ। ग्राम पंचायत स्तर की सोसायटियां सीधे जिला, राज्य और केंद्रीय सहकारी संस्थाओं से जुड़ गईं। चिट्ठी की जगह ई-मेल और बटन दबाते ही सहकारी सदस्यों के खाते में उनका हिस्सा पहुंचने लगा है। पैक्स समेत उच्च स्तर

की सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण होने से कारोबार में जहां सहूलियत हुई है, वहीं कार्य प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी हो गई है।

सहकारिता सुधार से सहकारी इकाइयों के कारोबारी कार्यक्षेत्रों का विस्तार हो गया है। उन्हें रसोई गैस, पेट्रोल पंप, बैंकिंग मित्र, राशन की दुकान (पीडीएस) चलाने, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और जन औषधि केंद्र चलाने जैसे दो दर्जन से अधिक क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई है। इससे जहां सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनने में लोगों का उत्साह बढ़ा है, वहीं कारोबारी लाभ मिलने लगा है। लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। लोगों का सहकारी संस्थाओं पर से टूटा भरोसा लौटने लगा है। ज्यादातर राज्यों में सहकारी संस्थाओं की लोकतांत्रिक प्रणाली कुछ लोगों के हाथों में कैद थी, चुनाव नहीं हो रहे थे, कानूनी अड़चनों के चलते नए लोगों को सदस्य बनाना संभव नहीं हो रहा था। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नये बायलॉज बनाकर सहकारी संस्थाओं के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं।

युवाओं के लिए सहकारी समितियां बनाने और स्टार्टअप शुरू करने की होड़ लगी है। सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) को ऋण प्रदान करने की क्षमता 25 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर सवा लाख करोड़ रुपये पहुंच चुकी है। तात्पर्य यह कि सहकारी संस्थाओं को अपने कारोबार के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने वाली है। सहकारी बैंकों के दिन बहुरने लगे हैं। उन पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने के साथ उनके नियमन की व्यवस्था कर दी गई है।

सहकारिता क्षेत्र में कानूनी सुधार, नियमों में सुधार, कार्य प्रणाली में सुधार के साथ उनके व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती को दूर करने की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्तर की सहकारी सोसायटियों के उत्पाद को बाजार मुहैया कराना भी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय स्तर की तीन ऐसी सहकारी सोसायटियां स्थापित की गई हैं, जिनका प्रभाव पैक्स स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देखने को मिलेगा। खाद्य सुरक्षा की दिशा में सहकारी क्षेत्र खेती के प्रमुख इनपुट उपलब्ध कराने से लेकर उपज के भंडारण के लिए गोदाम बनाने और

अतिरिक्त उत्पादन के निर्यात की भी योजना सिरे चढ़ने लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली भंडारण योजना के तहत सहकारिता क्षेत्र गांव-गांव में गोदाम बना रहा है। इससे कटाई के बाद फसलों के 27 प्रतिशत तक होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।

कृषि क्षेत्र की विकास दर स्थिर होने के मद्देनजर सहकारिता क्षेत्र मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। मछुआरा और पशुपालकों को भी किसान मानते हुए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। उनके लिए भी दो लाख प्राथमिक स्तर की सोसायटी के गठन का प्रावधान है ताकि उन्हें रियायती ऋण की सुविधा मिल सके, जिससे वे अपना कारोबार कर सकें।

सहकारिता के ताजा डेटाबेस के मुताबिक देश में लगभग 8 लाख सहकारी सोसायटियां है, जिनके 29 करोड़ से अधिक सहकार सदस्य हैं। कुल 11 तरह की सहकारी समितियां हैं, जिनमें प्राथमिक समितियों के अलावा ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशन के साथ जिला और राज्य स्तरीय सहकारी बैंक शामिल हैं। सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सहकारी बैंकों के दिन लौटने लगे हैं। नई शाखाएं खोलने के साथ वन टाइम सेटलमेंट जैसी सुविधाएं उन्हें मिल गई हैं। प्रजातांत्रिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश विकास की नई गाथा लिख रहा है। यह जन-जन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ कर विकसित भारत की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।■

सहकारिता सुधार से सहकारी इकाइयों के कारोबारी कार्यक्षेत्रों का विस्तार हो गया है। उन्हें रसोई गैस, पेट्रोल पंप, बैंकिंग मित्र, राशन की दुकान (पीडीएस) चलाने, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और जन औषधि केंद्र चलाने जैसे दो दर्जन से अधिक क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई है।

युवा विकास से राष्ट्र का विकास

राजेश पांडे

चेयरमैन, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

'युवा विकास से राष्ट्र विकास' के मंत्र से प्रेरित भारत की महानता, विकासशीलता, क्षमता और व्यवस्था को एक सफल और शाश्वत सत्य बनाने के ध्येय पर एनवाईसीएस न सिर्फ चलती है, ध्येय को जीती भी है। इसीलिए आज देश इसे एक सहकारी संस्था की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में समर्पित जीते जागते राष्ट्र पुरुष के रूप में देखता है।

'युवाओं की क्षमता अनुसार उन्हें विविध अवसर प्रदान कर सशक्त बनाते हुए भारत को विश्व भर में उसका सही स्थान दिलाना' आज देश का मंत्र है। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) अपनी शुरूआत से ही यानी करीब दो दशक से इसी विचारधारा के आधार पर कार्य कर रही है। व्यक्ति विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के समग्र एवं चौतरफा विकास से ही हम युवाओं को और इन युवाओं के माध्यम से देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। इस विशाल कार्य में सरकार को कई सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं आदि के सहभाग की जरूरत है। केवल सरकार की नीतियों और निर्णयों का समर्थन करने वाली जनता ही नहीं, बल्कि जनमानस के लिए कार्यान्वित की हुई किसी भी योजना में जन सामान्य की प्रत्यक्ष सहभागिता ही इन योजनाओं को सही अर्थ में पूर्णत्व प्रदान करेगी।

सरकार की कई योजनाओं में 'एनवाईसीएस इंडिया' कार्यान्वयन साथी के रूप में कार्यरत है। एनवाईसीएस को यह महत्वपूर्ण दायित्व और भूमिका सौंपते हुए देश ने, देश की सरकार ने इस संस्था में क्या देखा होगा? इसका सीधा जवाब है कि इस सहकारी संस्था के पास युवा शक्ति है, अपनी कार्यप्रेरणा से प्रेरित युवकों की टोली है और नवनिर्माण के उत्साह से भरपूर युवकों का समूह है। सोसायटी से जुड़े हर जिले के प्रतिनिधि ही इसकी शक्ति हैं और सार्थक बल हैं।

युवाओं के प्रेरणास्त्रोत स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, 'एक विचार उठाओ। उसे अपना जीवन बनाओ। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो और उसके लिए जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा रहने दें और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दें। यही सफलता का रास्ता है।' 'युवा विकास से राष्ट्र विकास' के मंत्र से प्रेरित भारत की महानता, विकासशीलता, क्षमता और व्यवस्था को एक सफल और शाश्वत सत्य बनाने के ध्येय पर एनवाईसीएस न सिर्फ चलती है, ध्येय को जीती भी है। इसीलिए आज देश इसे एक सहकारी संस्था की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में समर्पित जीते जागते राष्ट्र पुरुष के रूप में देखता है। भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए अपने पूरे सामर्थ्य से कार्यलीन संस्थाओं के बीच 'एनवाईसीएस इंडिया' की अपनी एक अलग पहचान बन रही है।

समाज की, समाज के हर युवा की और राष्ट्र की एनवाईसीएस से कुछ अपेक्षा है, कुछ उम्मीद है। उनकी अपेक्षापूर्ति के लिए सोसायटी तैयार है। युवाओं को कुशल और सक्षम बनाकर उन्हें रोजगार या उद्योग योग्य बनाने के लिए एनवाईसीएस कटिबद्ध है। एनवाईसीएस युवाओं को शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु जो आवश्यक कौशल अर्जन है वह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा महाराष्ट्र सरकार के साथ 'कौशल्य सेतु' के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के साथ विविध सेक्टर्स में छह महीने के छोटे ट्रेनिंग कोर्स चलाकर युवाओं को अच्छी आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है।

युवाओं को प्रेरित करने के लिए एनवाईसीएस समय-समय पर विभिन्न युवा एक्सपो का आयोजन करती रहती है। भारत में विकासात्मक योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने के लिए 2018 में युवा मंथन

नाम से दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं, युवा भारत को सशक्त बनाने और आने वाले दशक में युवाओं के लिए एक रोडमैप तैयार करने के मकसद से 2019 में दो दिवसीय रिसर्जेंट इंडिया युवा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव में युवाओं के आर्थिक समावेशन और सशक्तिकरण के लिए नीतियां बनाने के उद्देश्य से सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों, नीति निमार्ताओं और नागरिक समाज के विभिन्न हितधारकों ने इस दौरान भविष्य की रूपरेखा खींचने और उसे अमल में लाने का सफल प्रयास किया था।

'युवा एक्सपो' एनवाईसीएस का एक इवेंट मैनेजमेंट डिवीजन है। इसने 2006 और 2011 में नई दिल्ली में, 2008 में रायपुर में और 2013 में भोपाल में युवा कोऑपरेटिव एक्सपो का आयोजन किया था। इस एक्सपो में प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया और युवा सशक्तिकरण पर अपने बहुमूल्य अनुभव साझा किए। भारत में उद्यमिता और आर्थिक विकास में युवाओं की भूमिका बढ़ाने में ऐसे एक्सपो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं।

एनवाईसीएस के माइक्रोफाइनेंस डिवीजन ने अब तक कुल 95 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं, जो मुख्य रूप से सुलभ वित्तीय सहायता के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। सोसायटी के 8,000 सदस्यों ने पहले ही ऋण ले लिया है। यह विभाग देश के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 36 शाखाओं को संचालित करता है। ये शाखाएं महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में काम करती हैं, युवाओं को उनकी जरूरत के अनुसार वित्तीय समाधान पेश करती हैं और विभिन्न समुदायों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं।

एनवाईसीएस इंडिया देश में युवाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है। युवाओं में ऊर्जा का और खेलकूद जैसी गतिविधियों में प्रतिस्पर्धात्मकता की क्षमता का विकास होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। एथलीटों के लिए गेल रफ्तार इंडियन स्पीड स्टार के साथ-साथ एनवाईसीएस ने फुटबॉल के क्षेत्र में बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 'खेलेगी तो खिलेगी' मुहिम की शुरूआत की है। 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' के अंतर्गत देश भर में जन औषधि केंद्र स्थापित करते हुए स्वास्थ्य के साथ-साथ युवाओं को उद्यम विकास का अवसर मुहैया कराने में संगठन प्रयत्नशील है। युवाओं को उनकी क्षमता, पसंद और इच्छा अनुसार अवसर उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि वे भी परिवार, समाज, प्रदेश या राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम हो सकें। कौशल, उद्यमिता, खेल तथा स्वास्थ्य संबंधी इन योजनाओं से विश्वास है कि युवाओं को सकल विकास का वातावरण मिलेगा और इन प्रयत्नों से अभिप्रेरित होकर युवा ही युवाओं के लिए उन्नति और विकास के महाद्वार खोलेंगे।■

एनवाईसीएस ने फुटबॉल के क्षेत्र में बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 'खेलेगी तो खिलेगी' मुहिम की शुरूआत की है। 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' के अंतर्गत देश भर में जन औषधि केंद्र स्थापित करते हुए स्वास्थ्य के साथ-साथ युवाओं को उद्यम विकास का अवसर मुहैया कराने में संगठन प्रयत्नशील है।

सहकार से साकार हो रहा युवाओं का साझा लक्ष्य

देश के युवा संसाधन को कुशल श्रम संसाधन के तौर पर समृद्ध करने में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनवाईसीएस ऐसी संस्था है जो देश के युवाओं को प्रेरित करने तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए कार्य करती है। यह युवाओं के लिए स्वयं को सक्षम बनाने का एक मंच है।

यहां यह सवाल उठता है कि युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करेंगें? युवाओं का मार्गदर्शन कौन करेगा? और इन सबसे बढ़कर कि वे किस प्रकार के युवा होंगे जो देश के लिए अनुपातिक तौर पर सर्वाधिक योगदान दे पाएंगें, सरकार की सही योजनाओं से विकसित और विकासशील देशों में युवाओं की उर्जा का अब बेहतर सदुपयोग हो पा रहा है।

युवा सहकार टीम

किसी देश के भविष्य के बारे में जानना हो तो उस देश के युवाओं को जान लीजिए। इससे आप उस देश के भविष्य के बारे में सटीक भविष्वाणी कर पाएंगे। इस बात को लेकर दुनिया भर के समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री एकमत हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं की क्षमता के आधार पर तय होता है। जिस देश में जितने युवा होते हैं उसे उतने अवसर के तौर पर देखा जाता है। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, 'इस देश की ताकत इस देश के युवा हैं।'

भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 26 प्रतिशत जनसंख्या 10 से 24 साल की है। देश की कुल आबादी में सबसे ज्यादा 68 प्रतिशत आबादी 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग की है। 15 से 20 वर्ष के आयु वर्ग में 25.4 करोड़ युवा हैं। सर्वाधिक युवा शक्ति वाला (25.4 करोड़) यह आयु वर्ग देश में नई सोच, नए समाधान और नवाचार का बड़ा स्त्रोत बन सकता है। इन आंकड़ों के मद्देनजर भारत को दुनिया का सबसे अधिक उज्ज्वल भविष्य वाला देश माना जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी के दृष्टिकोण से भारत अपने सुनहरे दौर के बेहद करीब है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसे साकार रूप देने में युवा आबादी

की अहम भूमिका होगी। यह देखते हुए कि देश की तेजी से बढ़ती आबादी युवाओं द्वारा सशक्त हो रही है, प्रधानमंत्री का कहना है कि दुनिया इस बात को मानती है कि भारत आने वाले 25-30 वर्षों तक कामकाजी उम्र की आबादी के मामले में अग्रणी बनने जा रहा है। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक भी है और परिवर्तन की लाभार्थी भी है। यह देखते हुए कि ये युवा ही हैं जो भविष्य में नया परिवार और नया समाज बनाएंगे, प्रधानमंत्री मानते हैं कि युवाओं को यह तय करने का अधिकार है कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए।

कुशल श्रम शक्ति में बदल रही युवा शक्ति

यहां यह सवाल मौजूं है कि युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करेंगे? युवाओं का मार्गदर्शन कौन करेगा? और इन सबसे बढ़कर यह कि वे किस प्रकार के युवा होंगे जो देश के लिए अनुपातिक तौर पर सर्वाधिक योगदान दे पाएंगे? ये सवाल इसलिए है कि बहुत से ऐसे विकसित और विकाशील देश हैं जहां युवाओं की ऊर्जा का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे देशों में बड़े स्तर पर युवाओं की ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। भारत के युवाओं के बारे में भी यह राय बन रही थी कि युवाओं की अपार शक्ति की क्षमता का सदुपयोग हम नहीं कर पाएंगे। मगर हाल के वर्षों में भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद दुनिया नहीं कर रही थी। भारत की युवा शक्ति को कुशल श्रम शक्ति में बदलने का कार्य बहुत तेजी से हुआ है। कुछ वर्ष पहले तक भारत विश्व कुशल श्रम शक्ति के मामले में इकाई के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाता था, आज यह तस्वीर बदल चुकी है। विश्व बैंक के डेटा के अनुसार, भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर लगभग 25% है। यह आंकड़ा बता रहा है कि भारत युवा शक्ति के साथ कुशल श्रम शक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो चला है जिसमें पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक तौर पर बढ़ी है। एक सुखद संकेत यह भी है कि अभी के मुकाबले भारत की औसत कौशल श्रम शक्ति आने वाले पांच वर्षों में दोगुनी से भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

एनवाईसीएस की महत्वपूर्ण भूमिका

कई विभागों, एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों ने युवाओं को आर्थिक रूप से उत्पादक नागरिक बनाने की दृष्टि से कौशल प्रदान करने के लिए अन्य प्रोग्रामरों के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया है। हालांकि, यह महसूस किया गया है कि कौशल विकास के अलावा लाभकारी स्व-रोजगार के लिए सार्थक आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए युवाओं को परामर्श, वित्त,

भारत युवा शक्ति के साथ कुशल श्रम शक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो चला है जिसमें पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक तौर पर बढ़ी है। एक सुखद संकेत यह भी है कि अभी के मुकाबले भारत की औसत कौशल श्रम शक्ति आने वाले पांच वर्षों में दोगुनी से भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

एनवाईसीएस देश के युवाओं के आर्थिक विकास हेतु नई कल्पनाओं से नए क्षेत्रों के विकास पर जोर दे रही है। यदि नए क्षेत्रों का विकास किया गया, नई कल्पनाओं का सृजन किया गया तो युवाओं के लिए नए रोजगार तथा उद्यमिता के अवसर तैयार होंगे जो भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

संस्थागत और ढांचागत सहायता प्रदान करना आवश्यक होगा। हमारे देश के युवा अत्यधिक आदर्शवादी और शक्तिशाली परिवर्तन के वाहक हैं। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सतत आर्थिक विकास कार्यक्रम के लिए सहकारिता को सबसे प्रभावी संस्थागत तंत्रों में से एक माना जाता है। सहकारिता लोगों के लिए स्वयं को संगठित करने और एक लक्ष्य प्राप्त करने का औपचारिक तरीका है।

सहकारिता दो शब्दों सह और कारिता से मिलकर बना है। इसका अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना या अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना। समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं की सम्मिलित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। यही कारण है कि युवाओं के समान उद्देश्य की पूर्ति में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकार की भावना बढ़ने से उन्हें अपने क्षेत्र में काफी फायदा हो रहा है। सहकारिता में उदारता और पारदर्शिता दोनों हैं, इसलिए युवा इस ओर आकर्षित हो रहे हैं।

देश के युवा संसाधन को कुशल श्रम संसाधन के तौर पर समृद्ध करने में एनवाईसीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनवाईसीएस ऐसी संस्था है जो देश के युवाओं को प्रेरित करने तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए कार्य करती है। यह युवाओं के लिए स्वयं को सक्षम बनाने का एक मंच है। युवाओं को उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में सक्षम बनाना इसका प्रमुख उद्येश्य है। हाल के वर्षों में एनवाईसीएस ने इस क्षेत्र में सरहानीय कार्य किया है। एनवाईसीएस उद्मिता और रोजगार के साथ युवाओं को खेल व अन्य क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन देती है।

एनवाईसीएस देश के युवाओं के आर्थिक विकास हेतु नई कल्पनाओं से नए क्षेत्रों के विकास पर जोर दे रही है। यदि नए क्षेत्रों का विकास किया गया, नई कल्पनाओं का सृजन किया गया तो युवाओं के लिए नए रोजगार तथा उद्यमिता के अवसर तैयार होंगे जो भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

युवा कोऑपरेटिव का बेहतर स्ट्रक्चर हुआ तैयार

युवाओं के कौशल विकास के बारे में एनवाईसीएस के चेयरमैन राजेश पांडे का कहना है, 'देश में उत्साह के वातावरण का निर्माण हुआ है। हम कुशल श्रमशक्ति को विकसित करने में कामयाब हो रहे हैं। यही हमारा सबसे पहला उदेश्य है। आज हम एक मुकाम पर पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में हमारी युवा कोऑपरेटिव के काम की पद्धति बदलने जा रही है। देश में युवा कोऑपरेटिव का बेहतर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। करीब 600 जिलों में एनवाईसीएस का नेटवर्क फैल चुका है। हर जगह, हर जिले में कोई ना कोई एनवाईसीएस से जुड़कर काम कर रहा है। अब जरूरत है उस व्यक्ति के माध्यम से वहां के युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं बनाने की।■

सहकार बिना जीवन नहीं, युवा बिना सहकार नहीं

युवा देश का कर्णधार है जिन्हें देश का संचालन करना है। अपनी शक्ति, सामर्थ्य और साहस से देश को 'परम वैभव' तक पहुंचाने का दायित्व युवाओं को स्वीकारना है। युवाओं की ऊर्जा जीवन, यश पराक्रम अपराजेय, आस्था अडिग और संकल्प अटल होता है।

चंद्रशेखर पटेल
प्रभारी, मध्य प्रदेश एनवाईसीएस

युवा सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें विकास प्रक्रिया में सबसे आगे लाना है।

युवा भविष्य की कुंजी हैं। उनसे देश को बहुत उम्मीद है। सही मानसिकता और क्षमता के साथ युवा राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। युवा शक्ति हमारे राष्ट्र का गौरव है तथा हमारे राष्ट्र को विकास और उन्नति की ओर ले जाने के लिए एक सक्षम शक्ति है। देश की कुल आबादी का लगभग 65% हिस्सा युवा हैं। देश के युवाओं ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश को गौरवान्वित किया है। युवा शक्ति राष्ट्र का प्राण तत्व है। वही उनकी गति है, स्फूर्ति है और चेतना है। युवाओं की प्रतिभा, पौरुष, तप, त्याग और गरिमा राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। युवा वर्ग का पथ, संकल्प और सिद्धियां राष्ट्रीय पराक्रम और प्रताप के प्रतीक हैं। उनकी शक्ति अमर है। भारतीय युवाओं में ज्ञान की प्यास है और नई चीजें सीखने में उन्हें आनंद आता है। हमारे देश में युवा विज्ञान, तकनीक, खेल हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। युवा समाज के आधार हैं। युवा का विपरीत वायु होता है। एक युवा में वायु की शक्ति होती है।

युवाओं का गौरवशाली इतिहास

युवाओं ने कई गौरवशाली इतिहास रचे हैं। युवा शक्ति की देश-सेवा, समाज सेवा और

विश्व कल्याण की गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। आदिकाल से युवाओं ने ही भारतीय संस्कृति को विश्व तक पहुंचाया है। हमारे आराध्य आदि गुरु शंकराचार्य ने युवा अवस्था में ही वेदांत की शिक्षा पाकर लगभग 36 हजार किलोमीटर क्षेत्रफल वाले अखंड भारत की पद यात्रा करके भारतीय ज्ञान चिंतन के चार क्षेत्र बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम स्थापित कर ज्ञान की अविरल जोत जलाई थी। उस ज्योतिपुंज के वाहक स्वामी

विवेकानंद ने 11 सितंबर, 1893 को शिकागो की धर्म सभा में इसे महिमामंडित किया था।

कालजयी 'वंदे मातरम' के रचयिता भी एक युवा बंकिमचंद्र चटर्जी ही थे। युवाओं के हाथ में निर्माण भी होता है और विनाश भी। 1857 का संग्राम युवा रानी लक्ष्मी बाई, मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान की अमिट गाथा है। आजादी का महासंग्राम जहां युवा गांधी के सत्याग्रह के लिए जाना जाता है, वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां आदि जैसे कितने युवा थे जिनके अस्त्रों से अग्नि की ज्वालाएं फूटती थीं। उनके शौर्य और बलिदान की गाथाएं अमर हैं। युवा लोकमान्य तिलक ने पुणे के दगडू हलवाई के यहां 1893 में गणेश प्रतिमा की स्थापना के साथ ही 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' का उद्घोष करके ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी, जिसे बाद में बंगाल के तरुणाई नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' का आह्वान करके युवाओं की 'आजाद हिंद फौज' बनाकर इतिहास रचा।

भारत भूमि युवाओं की कौशल भूमि रही है। आर्यभट्ट और रामानुजम के गणित के सिद्धान्त वैश्विक धरोहर हैं। 14 वर्ष की अल्पायु में ही संत ज्ञानेश्वर ने श्रीमद्भगवद् गीता पर पूर्व भाष्य लिखकर सबको चमत्कृत कर दिया था। युवा मेजर ध्यानचंद, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम की प्रतिभा से खेल परिसर गुंजायमान हैं। वहीं भारतीय जाबांज सिपाहियों के सर्जिकल स्ट्राइक ने एक युवा भारत की शक्ति को विश्व के सामने प्रस्तुत किया।

भारत सरकार ने कोविड महामारी का सफलता पूर्वक सामना भी देश की युवा शक्ति के बल पर किया था। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को भोजन, पानी, आवास, गाड़ी आदि की सुविधाएं देश के युवाओं ने ही अपनी जान की परवाह न करके मुहैया कराई थी। कोविड के स्वदेशी वैक्सिन का सफल और कम समय में परीक्षण भी युवा वैज्ञानिकों ने ही किया। भरतीय युवाओं के मैनेजमेंट के सामने आज पूरा विश्व नतमस्तक है। ये युवा प्रबंध का ही कमाल है कि 14 जनवरी, 2021 से 31 अगस्त, 2022 के 18 महीनों में ही देश के लोगों को दो सौ करोड़ वैक्सीन के डोज लगानो में सफलता मिली जो एक चमत्कार है।

भारत में युवा सशक्तिकरण

युवा सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें विकास प्रक्रिया में सबसे आगे लाना है। इससे राष्ट्र निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। युवा सशक्तिकरण का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, साहसिक कार्य,

युवा सशक्तिकरण की आवश्यकता

युवाओं का सशक्तिकरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सही मार्गदर्शन देकर हम युवा ऊर्जा का समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक उपयोग करके राष्ट्र को सक्षम, सशक्त बनाने के साथ ही युवाओं को जिम्मेदार भी बना सकते हैं। युवा सशक्तिकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें देखकर किशोरों को भी प्रेरणा मिलती हैं। युवाओं को लाभार्थी बनने की बजाय देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। युवा दिमाग को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई थी। इस तरह की पहल से युवाओं की क्षमता को सही दिशा में निर्देशित किया जाता है और बदले में वह पूरे देश को मजबूत करने में मदद करता है।

युवा सशक्तिकरण के कुछ लाभकारी परिणामों में सशक्त और कुशल युवा, वंचितों के लिए स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाला जीवन, युवाओं की आत्म-प्रभावकारिता और बेहतर सामाजिक कौशल, राष्ट्रीय विकास, उद्यमशीलता, युवा समुदायों द्वारा सरकार पर कम निर्भरता शामिल हैं। युवाओं द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को अपनाने से अर्थव्यवस्था में कौशल की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही युवाओं को स्व-रोजगार के लिए साधन प्रदान किए जा सकते हैं। युवाओं को सशक्त बनाने से देश के बढ़ते बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी कौशल की आपूर्ति भी बढ़ सकती है।

युवा बेरोजगारी, गरीबी और भूख अब वैश्विक मुद्दे हैं जिनसे दुनिया भर की सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं निपटने की कोशिश कर रहे हैं। युवा आज का नागरिक है। उनके द्वारा किए गए कार्य न केवल वर्तमान को, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। युवा सहकार के माध्यम से देश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही। फूड कोर्ट, अतुल्य चाय, ऑनलाइन डिलीवरी ऐप युवा तकनीक का ही कमाल हैं।

युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास, किशोरों का विकास और सशक्तिकरण, तकनीकी और संसाधन विकास को बढ़ावा देना है। युवा प्रतिभा को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई थी। इस तरह की पहल के माध्यम से युवाओं की क्षमता को सही दिशा में निर्देशित किया जाता है जो पूरे देश को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होता है। युवा सशक्तिकरण में निवेश करने का इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के लिए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपने गेम चेंजर अभियान 'स्टार्ट-अप इंडिया' और 'स्टैंड-अप इंडिया' का अनावरण किया था। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना 2022 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के रूप में लोगों के रेखांकित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का लाभ देने का प्रयास है ताकि उन्हें राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। इसी तरीके से सहकारिता के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में युवा किसानों एवं उन्नत किसानों के लेकर भी अनेक योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और मार्गदर्शन के अनुसार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश भर में युवा विकास और सशक्तिकरण योजना के तहत कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है क्योंकि आत्मनिर्भर युवा एक-दूसरे से सीख कर नए अवसर व संसाधन खोजने तथा आत्मविश्वास एवं क्षमताओं का निर्माण करना सिखाते हैं।

देश के युवाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक कौशल और ज्ञान का विकास करना, उनकी छिपी क्षमता को जगाना, उन्हें समाज की समस्याओं से अवगत कराना और उन्हें यह सिखाना है कि वे समस्याओं को दूर करने में कैसे योगदान दे सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि योजना और निर्णय लेने में युवाओं की भागीदारी खुद को और दूसरों को प्रभावित करती है। जैसे स्कूलों, स्थानीय सरकारों और संगठनों की संरचना, संस्कृति और प्रोग्रामिंग तब बहुत मजबूत होती है जब युवा इसमें शामिल होते हैं, न केवल उपभोक्ताओं या लाभार्थियों के रूप में, बल्कि विकास और निर्णय लेने में भागीदार के रूप में युवाओं की भूमिका भी अहम होती है।■

युवा सशक्तिकरण का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, साहसिक कार्य, युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास, किशोरों का विकास और सशक्तिकरण, तकनीकी और संसाधन विकास को बढ़ावा देना है। युवा प्रतिभा को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई थी।

ग्रामीण विकास में सहकारी बैंकों की अहम भूमिका

देश के 19 राज्यों के प्रत्येक जिले को कवर करने के लिए खुलेंगे नए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक

नाबार्ड के मुख्यालय में सहकारी विकास की मौजूदा योजनाओं की प्रगति पर गंभीर मंथन किया गया

युवा सहकार टीम

सहकारिता ग्रामीण विकास की सबसे प्रमुख आधारशिला है। इसीलिए देश में सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास हो रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष भूटानी ने सहकारी बैंकिंग से संबंधित मुद्दों और मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर चर्चा के लिए विभिन्न सहकारी हितधारकों के साथ बैठक की। मुंबई में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रधान कार्यालय में केंद्रीय सहकारिता सचिव ने बैंकरों से मुलाकात की और उन्हें मंत्रालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। बैठक के दौरान, देश के 19 राज्यों के प्रत्येक जिले को कवर करने के लिए नए डीसीसीबी खोलने, ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा रूपे क्रेडिट कार्ड जारी करने, सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन और अन्य पर चर्चा की गई। दरअसल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (डीसीसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित एक ग्रामीण सहकारी बैंक है जो देश के विभिन्न हिस्सों में जिला स्तर पर संचालित होता है। बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से यह बात सामने आई कि नाबार्ड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से अनुरोध किया था कि वह आरबीआई के वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को पूरा करने वाले सभी पात्र अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति देने पर विचार करे।

इस मौके पर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससी बैंक) के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष विद्याधर अनस्कर ने कहा कि इस सार्थक बैठक में महाराष्ट्र राज्य सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के साथ ही देश भर में सहकारिता को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडारण के कार्यान्वयन के बारे में भी विमर्श हुआ। सहकारी दिग्गजों के बीच श्री अनस्कर ने कहा कि नासिक डीसीसीबी ने उच्च क्षमता के सहकारी गोदाम बनाने के लिए 52 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को चुना गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन पैक्स को गोदाम बनाने के लिए एमएससी बैंक द्वारा सीधे वित्त की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एमएससी बैंक डीसीसीबी को अत्याधुनिक आईटी संचालन और सहायता सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सिंधुदुर्ग डीसीसी बैंक महाराष्ट्र के डीसीसी बैंकों में पहला डीसीसी बैंक है जो एमएससी बैंक के साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र से संबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दूसरे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) भी एमएससी बैंक के साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र से संबद्ध हो जाएंगे। सहकारी हितधारकों की बैठक में डीसीसीबी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने पर भी विचार-विमर्श किया गया। लेकिन, इसे तकनीकी आधार पर संभव नहीं पाया गया। इसके संदर्भ में यह मत व्यक्त किया गया कि सभी डीसीसीबी एक छत्र के नीचे काम करते हैं। राज्य सहकारी बैंक पहले से ही एसटीसीबी अनुसूचित स्थिति का लाभ उठा रहे हैं।■

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Did You Know?

2025 is the International Year of Cooperatives!

The UN declared 2025 as a year to celebrate cooperatives around the world. Cooperatives are businesses owned by their members, focusing on both profit and the needs of their communities. They play a big role in sustainable development and achieving the UN's Sustainable Development Goals by 2030.

There will be a year-long celebration to raise awareness about cooperatives and their positive impact.

facebook.com/kribhco.pr @kribhco_pr @kribhcopr5573

MALABAR

PROMISE

At Malabar Gold & Diamonds, our core philosophy prioritizes customers, committed to delivering exceptional quality and crafting customer-centric policies. We proudly call it the Malabar Promise, an assurance that lasts forever.

COMPLETE TRANSPARENCY
Totally transparent and detailed invoice and price tag. Each piece of jewellery has an accurate price tag which indicates gross weight, stone weight, net weight, stone charge and making charge.

ASSURED LIFETIME MAINTENANCE
We assure lifetime maintenance for jewellery from all our 350 plus stores across 13 countries.

100% VALUE ON GOLD EXCHANGE
We give you full value, without any deductions, when you exchange gold jewellery purchased from us.

100% VALUE ON DIAMOND EXCHANGE
Assured 100% exchange value for diamond jewellery purchased from us.

TESTED & CERTIFIED DIAMONDS
Every diamond passes through 28 internal quality tests with IGI- GIA certification.

GUARANTEED BUYBACK
Buyback guarantee for all gold and diamond jewellery.

COMPLIMENTARY INSURANCE
Assured insurance for 1 year against any loss by burglary, fire and extortion.

100% HUID COMPLIANT GOLD
We guarantee the purity of our gold jewellery with 100% HUID hallmark certification.

RESPONSIBLY SOURCED PRODUCTS
Sourced responsibly to protect the environment and stakeholders across manufacturing, sourcing, bullion and final product.

FAIR LABOUR PRACTICES
Fair wages, benefits and working conditions for artisans.

FAIR PRICE POLICY
Reasonable making charges for all jewellery which assures best value for purchase.

*Above Promises are valid for jewellery purchased from Malabar Gold & Diamonds only.

MALABAR GOLD & DIAMONDS
CELEBRATE THE BEAUTY OF LIFE

THE RESPONSIBLE JEWELLER

A PROMISE IS A PROMISE

Terms & Conditions apply

Call: 1800 572 0916 | BUY ONLINE AT: malabargoldanddiamonds.com
OVER 350 STORES ACROSS 13 COUNTRIES